पश्चिम बंगाल में रक्तिम नक्षत्रोदय

पश्चिम बंगाल में रक्तिम नक्षत्रोदय

राम स्वरूप

अनुवादक: सौरभ अग्रवाल

वॉयस ऑफ इंडिया

नई दिल्ली

© वॉयस ऑफ इंडिया
सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम हिन्दी संस्करण, 2024

ISBN 978-93-85485-43-5

Hindi translation of "Red Star Over West Bengal"
पश्चिम बंगाल में रक्तिम नक्षत्रोदय
लेखक: रामस्वरूप; अनुवादक: सौरभ अग्रवाल

प्रकाशक :
वॉयस ऑफ इंडिया
2/18, अन्सारी रोड,
नई दिल्ली – 110 002

Website: www.voiceofin.com

Published by Voice of India, 2/18, Ansari Road, New Delhi – 110 002.
Printed at D.K. Fine Arts Press Pvt. Ltd., Delhi – 110 052.

पश्चिम बंगाल में रक्तिम नक्षत्रोदय

1. भारत में चुनाव के पश्चात् का परिदृश्य स्पष्ट रूप से बदला हुआ है। राजनीतिक सत्ता पर काँग्रेस के एकाधिकार के लुप्त होने के साथ, कई राज्यों में राजनीतिक गठबंधन का एक अव्यवस्थित संग्रह हमारे समक्ष प्रकट हुआ है। किसी न किसी राज्य में कम के कम एक मंत्री के प्रतिनिधित्व रूप में, हर राजनीतिक दल, बड़ा या छोटा, अब सत्ता में है। देश अभी तक गुटीय राजनीति से परिचित हुआ है। पर अब हमारा परिचय लगातार सत्ता परिवर्तन और रातों-रात पार्टी '*लेबल*' बदलने की '*टर्न-कोट*' अवसरवादी राजनीति से होगा। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि देश विचारधारा के सन्दर्भ में न तो वाम (बाएँ) है और न ही दक्षिण (दाएँ) है, वरन् स्थानीय और क्षेत्रीय हो गया है, राजनीतिक क्षितिज संकीर्ण हो गया है और हमारी चेतना अल्पवयस्क-तुच्छ हो गई है।

2. हमारे भारत के सत्रह राज्यों में से आठ में ग़ैर-काँग्रसी सरकारें स्थापित हो चुकी हैं। केरल और पश्चिम बंगाल के दो राज्यों को छोड़कर, ये, सरकारें सामान्य तौर पर ग़ैर-कम्युनिस्ट हैं, जो काँग्रेस की जनमानस द्वारा आम अस्वीकृति के आधार पर तथा काँग्रेस के विरोध में एक साथ एकत्रित हुई पार्टियों द्वारा बनाई गई हैं। उनकी विचारधारा का रंग चाहे जो भी हो, मेरे अंतिम विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार पर मैं यह कह सकता

हूँ कि सभी सरकारें देशभक्त और विधि–कानून का पालन करने वाली हैं और संभवत: खिन्नचित्त–अवसादग्रस्त बिहार को छोड़कर, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरश: पालन करेंगीं एवं भारतीय संविधान की गरिमा को यथावत कायम रखेंगी।

3. दो कम्युनिस्ट–प्रभुत्व वाले राज्यों में से, केरल आर्थिक रूप से अविकसित है। इसके पास नाममात्र के लायक भी कोई औद्योगिक सर्वहारा नहीं है। केरल किसी भी कम्युनिस्ट देश की सीमा पर स्थित नहीं है और अत: इसका कोई ''सुरक्षित पृष्ठ भाग'' नहीं है। अत: इन परिस्थितियों में कम्युनिस्ट रणनीति को जनता के समक्ष अपनी योग्यता को प्रमाणित करना होगा।

4. इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल न केवल अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, वरन् अत्यधिक असुरक्षित भी है। यह सिक्किम, भूटान, नेपाल और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा को छूने वाला एक सीमावर्ती रणनीतिक राज्य है और एक प्रमुख समुद्री मार्ग का मुख है। 1911 सीई तक, अविभाजित भारत की राजधानी कलकत्ता, इसी बंगाल राज्य में स्थित थी। अभी हाल ही के समय तक, पश्चिम बंगाल औद्योगिक रूप से भारत का सर्वाधिक उन्नत भाग था। कलकत्ता अभी भी भारतवर्ष का सर्वाधिक बड़ा नगर और सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह है। 'बंगाल' भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रणी और भारतीय पुनर्जागरण का उद्गम स्थल रहा है। यद्यपि वर्तमान में पश्चिम बंगाल का गौरव आज सुवर्ण–हिरण्य अतीत के रूप में ही सिमट कर रह गया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल दु:ख एवं विषाद का अनुभव कर रहा है। भौगोलिक रूप से पश्चिम बंगाल राज्य को काट–छाँट कर छोटा कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या थी तथा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व भी है; इसके साथ पश्चिम बंगाल में जनसंख्या

वृद्धि दर भी अधिक है और इस स्थिति में पश्चिम बंगाल राज्य को पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए अतिरिक्त 5 मिलियन (50 लाख) शरणार्थियों को आश्रय-आतिथ्य देना पड़ रहा है। किसी अन्य भारतीय राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल राज्य की सामाजिक संरचना भी अधिक एवं अत्यधिक अशक्त-निर्बल है। पश्चिम बंगाल राज्य सामाजिक अव्यवस्था से दो-चार हो रहा है, जो अपरिहार्य सामाजिक अन्याय को उत्पन्न कर रहा है। भारत-पाकिस्तान युद्ध, भारत-पाकिस्तान विभाजन त्रासदी और सरकारी योजनाओं ने पश्चिम बंगाल राज्य में नए वर्गों—नए संभ्रांत-धन्नासेठों और नए दरिद्र-निर्धनों को जन्म दिया है। पश्चिम बंगाल राज्य का पारंपरिक स्वरूप और वहाँ निवासरत मनुष्यों के मध्य परस्पर सम्बन्ध ध्वस्त-खंडित-कटु हुए हैं यद्यपि नए स्वरूप अभी तक सृजित नहीं हो पाए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में गरीबी और अमीरी की पराकाष्ठा है। यदयपि पश्चिम बंगाल राज्य जूट, कोयला, चाय और इंजीनियरिंग जैसे हमारे भारतवर्ष के पारंपरिक उद्योगों का घर है परन्तु पश्चिम बंगाल राज्य में प्रयुक्त औद्योगिक प्रौद्योगिकी काफी हद तक आदिम है। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रबंधन निम्न कार्यकुशलता का पर्याय बन गया है और उद्यमिता में सच्ची अग्रणी औद्योगिकीकरण भावना का अभाव है। वस्तुत: पश्चिम बंगाल राज्य में उद्यमिता वर्तमान में सट्टबाजी और क्रय-विक्रय व्यापार तक ही सीमित हो गई है। पश्चिम बंगाल राज्य में मजदूरों (श्रमिकों) को कम मजदूरी (पारिश्रमिक) देकर कार्य कराया जाता रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे पड़ोसी राज्यों से पश्चिम बंगाल राज्य में सस्ते श्रमिकों का सतत आगमन वृहद् स्तर पर हो रहा है अत: पश्चिम बंगाल राज्य में मजदूर (श्रमिक) निम्नतम मजदूरी (पारिश्रमिक) में भी कार्य करने के लिए सहमति दे रहे हैं। यह बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित परिस्थितियाँ,

श्रमिकों के मध्य दु:ख-निराशा-क्रोध-विद्रोह की भावनाओं को उत्पन्न कर रही हैं। शिक्षित युवाओं में वृत्तिहीनता-अनुद्योगिता (बेराज़गारी) दर भयावह स्तर तक पहुँच गई है। पश्चिम बंगाल राज्य में सार्वजनिक सेवाओं का स्तर सदैव से ही दयनीय रहा है और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित कुछ सार्वजनिक सेवाओं को छोड़कर, पश्चिम बंगाल राज्य में नागरिक सुविधाएँ, जैसे पेयजल, जल निकासी, स्वच्छता, चिकित्सालय आदि पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हैं। किसी अन्य भारतीय राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल राज्य में विकासहीनता और पतन अधिक स्पष्ट है। किसी अन्य भारतीय राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल राज्य में सतत-स्थिर विकास और साझा समृद्धि की संभावनाएँ निरंतर धूमिल होती जा रही हैं।

5. पश्चिम बंगाल राज्य में आदिम पूँजीवाद की समस्याएँ पहले से थीं पर राज्य की नौकरशाही में लालफीताशाही की उत्तरोत्तर वृद्धि ने समस्याओं को और भी अधिक विकट बना दिया है। पश्चिम बंगाल राज्य में अप्रचलित-पिछड़ी औद्योगिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण उत्पादकता निरंतर घट रही है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार स्वयं के समाजवादी होने का दावा कर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नित्य नए नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों के दायरे में लाने में प्रयासरत है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयों से सम्बंधित '*.फ़ाइलें*' पश्चिम बंगाल राज्य के सरकारी मंत्रालयों में धूल खा रहीं हैं। अत: इसके फलस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों की उत्तरजीविता के लिए काल बनता जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ बड़े पैमानों पर की जा रही हैं परन्तु इसकी तुलना में सार्वजनिक सेवाओं में उन्नयन-समुन्नति परिलक्षित नहीं हो रही है। अत: पश्चिम बंगाल राज्य के

वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है तथा 'वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर)' निरंतर घट रहा है।

बंगाली युवा भी आत्म-विमुख हो रहे हैं। वे पाते हैं कि उनकी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाएँ मानव-निर्मित वातावरण के सर्वथा अनुरूप नहीं हैं। उन्हें कविता लिखना, चित्रकारी करना, संगीत सुनना, गायन एवं वादन में दिन-रात संलग्न रहना तथा अल्हड़-मस्त जीवन जीना पसंद है। यद्यपि पश्चिम बंगाल राज्य का नया वातावरण उनसे नीरस, नियमित रूप से कार्यालयों में परिश्रम करने की अपेक्षा कर रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकांशत: निवासी कठोर परिश्रम से इतर दिन-रात केवल भोग-विलास का "अनुभव करने में" अथवा "विचार-चिंतन" करने में संलग्न रहना चाहते हैं। यद्यपि उनके ये दोनों व्यवहार 'लक्षित उत्पादकता के प्रति समर्पित औद्योगिक संस्कृति' के उत्थान के विरुद्ध हैं। उनके इस अकर्मण्य व्यवहार से 'लक्षित उत्पादकता एवं औद्योगिक संस्कृति' दुष्प्रभावित हो रही है। पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकांशत: निवासी व्यक्तिगत संबंधों एवं कार्यों को अधिक महत्त्व देते हैं परन्तु उद्योग और नौकरशाही घोर रूप से असंवेदनशील और अवैयक्तिक हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में संव्यावसायिक संबंधों एवं कार्यों की उपेक्षा में सतत रूप से अभिवृद्धि हो रही है।

6. एक 'बांग्ला भाषी' बंगाली को लग रहा है कि वह अपने वोट के बावजूद अपने आर्थिक निवास स्थान एवं अपने राजनीतिक वातावरण का सृजन करने में भी सर्वथा असमर्थ है। करीब चार महीने पहले उन्हें मतदान करने के लिए आहूत किया गया था। बढ़ती कीमतों से दु:खी होकर, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की कमी से दु:खी होकर, राशन और नियंत्रण की समस्याओं से चिंतित होकर उन्होंने अपना वोट काँग्रेस और काँग्रेस के

विरोधी असंतुष्टों (दोनों ने पश्चिम बंगाल राज्य में 280 सदस्यों के विधानसभा सदन में 165 सीटें प्राप्त की हैं) के मध्य विभाजित किया है। पश्चिम बंगाल राज्य के मतदाताओं के वोट का '*पैटर्न*' अतीत से बहुत पृथक नहीं था, उन्होंने वस्तुतः कांग्रेसियों को ही चुना था। परन्तु मत विभाजन के कारण परिणाम अत्यधिक पृथक-अलहदा थे। कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों शाखाओं की संयुक्त शक्ति केवल 59 विधानसभा सदस्यों की थी, जो कि विधानसभा सदन में केवल 21% का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार यद्‌यपि अधिकांशतः बंगाली मतदाताओं ने कम्युनिस्ट विचारधारा को राज्य सत्ता पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए वोट नहीं दिया था, वस्तुतः उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को सत्ता प्राप्त करने से रोकने के लिए वोट दिया था। तथापि खंडित जनादेश एवं अनेक बेमेल दलों के एक साथ आने तथा विचित्र अंकगणित के उत्पन्न होने के पश्चात् बंगाली मतदाताओं ने ख़ुद को ठगा महसूस किया क्योंकि उनका पश्चिम बंगाल राज्य कम्युनिस्टों के नियंत्रण में चला गया है।

7. एक संयुक्त मोर्चा सरकार, 14 पार्टियों का एक अजीब-सा बेमेल मिश्रण, काँग्रेस सरकार को हटाकर सत्ता में आई है। इस गठबंधन में, वामपंथी कम्युनिस्ट, जो पूरी तरह से अल्पसंख्यक थे, एक प्रमुख प्रभाव प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इस सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य की किसी भी पुरानी समस्या का समाधान नहीं किया है और इन समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी प्रारंभिक कार्य करने के प्रयास से भी सर्वथा परहेज़ किया है। यह एक विशद्ध स्वार्थपरकता से अभिभूत राजनीतिक सरकार है और रचनात्मक राष्ट्र-निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने के बजाय चुनाव-पूर्व भय, शोर और आरोपों का वातावरण बनाए रखना पसंद करती है। वह विशेष रूप से उन वर्गों के मध्य अपना राजनीतिक आधार सुदृढ़ करने में

लगी हुई है, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी पहले से ही अपना आधार बना चुकी है। नीतिगत घोषणाओं और उपायों की पूरी शृंखलाएँ, मुख्य रूप से इन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अपने राजनीतिक लक्ष्यों को मुख्य तथा आवश्यक आर्थिक परिणामों को गौण महत्त्व दे रही है। कम्युनिस्ट पार्टी वस्तुतः भारत का विध्वंस कर के केवल अपनी अराजक नृशंस छल-कपट की विचारधारा को सशक्त करने के लिए प्रयासरत एवं कटिबद्ध है।

8. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार में मजबूती से अपनी पकड़ बनाने के पश्चात् कम्युनिस्ट पार्टी धीरे-धीरे अपने नृशंस कार्यक्रमों को सामने ला रही है। तथाकथित क्रांति के वर्तमान चरण में कम्युनिस्ट पार्टी का प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम बंगाल के समाज में विद्यमान सहिष्णु सामाजिक व्यवस्था और उसके सहायक अंगों को छिन्न-भिन्न करना है। कम्युनिस्ट पार्टी इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ग युद्ध और वर्ग घृणा को तीव्र करने में, ''वर्ग शत्रु'' को हतोत्साहित करके उसे भ्रम में डालने में तथा भूखी जनता के मध्य क्रांति के बीज बोकर उनमें विद्रोह की ज्वाला भड़काने में संलग्न है। कम्युनिस्ट पार्टी की मंशा चौतरफा अराजकता, अशांति, अव्यवस्था तथा विघटन को प्रोत्साहित करने की है। यद्यपि इस भ्रम की स्थिति में भी कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र एकजुट संगठित शक्ति बनी रहेगी जो पश्चिम बंगाल राज्य को क्रांति की राह पर ले जाएगी।

9. ''प्रजातान्त्रिक लोकतंत्र (*पीपुल्स डेमोक्रेसी*)'' की आयु, लोगों के विचार से अल्प है। प्रजातान्त्रिक लोकतंत्र का प्रारंभ सदैव असमान और बंधनमुक्त तत्वों के संयुक्त रूप के परिणामस्वरूप होता है; जिसे समृद्ध, साधन संपन्न, घोर-अनुशासित कम्युनिस्ट पार्टी सरलता से निर्देशित कर सकती है तथा उसको नेतृत्व भी प्रदान कर सकती है। एक बार जब

कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं को प्रजातान्त्रिक लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता के शीर्ष पर स्थापित कर लेती है, तो कम्युनिस्टों को सत्ता से पदच्युत करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। इस चरण में, कम्युनिस्ट पार्टी सरकारी कोष को लेकर अत्यधिक उदार होती है। सरकारी कोष के अपव्यय के माध्यम से कम्युनिस्ट, दीन-दरिद्रों की भक्ति तथा निम्न-कनिष्ठ नौकरशाही की निष्ठा को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। दीन-दरिद्रों की भक्ति तथा निम्न-कनिष्ठ नौकरशाही की निष्ठा को अर्जित करने के लिए कम्युनिस्ट, सरकारी कोष को खाली करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, अराजक तत्त्वों को समाज और प्रशासन में निहित नियमों की अभिव्यक्ति और अनुशासन के मापदंडों को नष्ट करने के लिए ''लोकतांत्रिक अधिकारों'' का दुरुपयोग करने की पूरी छूट देती है। यद्यपि जब कम्युनिस्ट पार्टी का अगला ''उच्च चरण'' प्रारंभ होता है, तो उन्हीं अधिकारों की माँग करने वाले उनके लिए ''प्रतिक्रियावादी'' हो जाते है। श्रमिकों द्वारा पारिश्रमिक में वृद्धि की माँग को तब कम्युनिस्ट ''अश्लील अर्थव्यवस्थावाद'' के रूप में चिह्नित कर नकार देते हैं और कम्युनिस्टों के पक्षसमर्थकों द्वारा 'स्वतंत्र विचारों[1] से अभिप्रेरित होकर मतदान करने की अभिलाषा को ''संशोधनवाद'' एवं ''विद्रोह'' के रूप में निरूपित किया जाता है।

10. कम्युनिस्ट स्वयं को समाज की धात्री[2] के रूप में स्थापित करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांति की ''स्वतः प्रवृत्ति'' में विश्वास नहीं करती है।

---

[1] *अनुवादक की टिप्पणी*—संसदीय विभाजन जिसमें सदस्य किसी पार्टी की नीति का पालन करने के बजाय अपनी मान्यताओं के अनुसार मतदान करते हैं।

[2] *अनुवादक की टिप्पणी*—शिशु जन्म की प्रक्रिया में गर्भवती महिला की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति।

कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि जनमानस का नेतृत्व उन्हें पूर्णत: वश में करके अर्थात् पूर्ण रूप से नियंत्रित या प्रभावित करके किया जाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांति की रणनीति को सावधानीपूर्वक तैयार करने में विश्वास रखती है। कम्युनिस्ट पार्टी, आवश्यकता और अवसर के अनुसार अपनी रणनीति को विकसित और विविधता प्रदान करने में भी विश्वास रखती है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास सुनियोजित क्रांति की ज्वाला को प्रज्ज्वलित करने का एक विस्तृत ख़ाका है। जिस प्रकार एक शानदार ढंग से प्रबंधित आधुनिक औद्योगिक निगम सतत एवं नियमित रूप से व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण, बिक्री पूर्वानुमान, उत्पाद अनुसंधान आदि कार्यों में संलग्न रहता है उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी भी सतत एवं नियमित रूप से मनुष्य और उसके समाज का '*इनपुट-आउटपुट*' विश्लेषण करती रहती है।

11. अपने तीन महीने के संक्षिप्त शासनकाल के दौरान वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने तात्कालिक कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणीत करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान में जिस प्रकार की '*संगठित गतिविधियों*' में रत है तथा कम्युनिस्ट पार्टी की कुटिल नीति की दिशा और भविष्य में घटित होने वाले घटनाक्रमों के स्वरूप को एक संक्षिप्त विवरण के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित तथ्यों से जो चित्र स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है, वह निर्णायक संघर्ष के लिए कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कट्टरपंथी तैयारियों, सामूहिक प्रतिबंधों, हिंसक उथल-पुथल और आतंक के नए हथियारों के निर्माण का है।

(i) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक श्रमिक अभी तक पूरी तरह से संघबद्ध एवं लाभबंद नहीं हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम उद्देश्य

कम्युनिस्ट प्रभुत्व वाले ट्रेड यूनियनों की एजेंसियों के माध्यम से, बड़े और छोटे कारखानों के प्रबंधन को डरा-धमका कर कम्युनिस्टों के माँगपत्र के अनुसार उनके यहाँ कार्यरत सभी श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों में सम्मिलित कर के पूर्ण संघीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अराजक आंदोलनात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करके लक्षित कारखानों के सभी श्रमिकों को अपनी कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनों के दायरे में लाना तथा उन्हें अपनी विचारधारा के व्यापक-प्रसार हेतु सक्रिय रूप से सम्मिलित करना, कम्युनिस्ट पार्टी की मूल रणनीति है। वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी की इस मूल रणनीति के तहत, पश्चिम बंगाल राज्य के कारखानों, बागानों और कोयले की खदानों में अत्यधिक सुव्यवस्थित और ठोस प्रयास चल रहा है।

(ii) कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व वाली 'इंटक'[3] या 'हिंद मजदूर सभा'[4] से संबंधित मौजूदा यूनियनों पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा क़ब्ज़ा किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व वाली 'इंटक' या 'हिंद मजदूर सभा' यूनियनों के कार्यकर्ताओं पर खुलेआम हमले किए जा रहे हैं क्योंकि पुलिस पीड़ितों को कोई भी सुरक्षा देने में डर अथवा झिझक रही है।

---

[3] *अनुवादक की टिप्पणी*—इंटक यानी 'भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस', भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन महासंघ है। इसकी स्थापना 3 मई, 1947 को हुई थी। यह कांग्रेस की श्रमिक शाखा है और इसका ध्येय भारत के श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना और उन्हें समानता का अधिकार दिलाना है।

[4] *अनुवादक की टिप्पणी*—हिंद मजदूर सभा (एचएमएस) का गठन 1948 सीई में समाजवादियों द्वारा किया गया था, लेकिन इसका सोशलिस्ट पार्टी से कोई खास संबंध नहीं है। यह भारत में सबसे कम राजनीतिक और सबसे व्यावहारिक ट्रेड यूनियन संघों में से एक है।

(iii) कम्युनिस्टों का लक्ष्य घेराव की सर्वसत्तात्मक पद्धति के व्यापक उपयोग के माध्यम से नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य मानवीय और लोकतांत्रिक संबंध को नष्ट करना है।

(iv) नगरों में बैंकों, बीमा कंपनियों और व्यापारिक कंपनियों में बहुत तीव्रता से श्रमिकों का संघीकरण किया जा रहा है। इन कर्मचारी यूनियनों के माध्यम से उनके प्रबंधन को अधीनता स्वीकार करने तथा कम्युनिस्टों के शीर्ष नेतृत्व की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों को धीरे-धीरे वर्ग संघर्षों और सतत युद्ध के क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। किसानों के सामाजिक वर्गों को एक-दूसरे के विरुद्ध निरूपित किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर ज़मीन के भूखे किसानों को दूसरों की अथवा सरकारी ज़मीनों पर बलात् कब्ज़ा करने, फ़सलों को लूटने, भूमि के मालिकों को आतंकित करने और पुलिस के साथ संघर्ष करने के लिए उकसाया जा रहा है। अन्य स्थानों पर सीमान्त किसानों, बंटाईदारों[5] और छोटे-मझोले किसानों को बड़े किसानों के विरुद्ध एकजुट किया जा रहा है।

(vi) पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में शैक्षिक प्रतिष्ठानों को छात्र निकायों और शिक्षक संघों द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है।

(vii) शिपिंग, डॉक्स, रेलवे, सड़क परिवहन और ट्राम-वे जैसे सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं को कम्युनिस्ट यूनियनों के माध्यम से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक आदेश पर 'संचार की धमनियों' को पंगु, नष्ट और बाधित कर सकते हैं।

---

[5] *अनुवादक की टिप्पणी*—जो किसान, भूमि के मालिक को धन देकर या उससे उपज में हिस्सा तय करके उसका खेत लेकर एक विशेष कालावधि तक जोतते हैं।

(viii) कम्युनिस्ट प्रेस और कम्युनिस्ट मंचों से प्रशासन और पुलिस में कार्यरत सुदृढ़-कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों पर लक्षित करके हमला किया जा रहा है। इन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को स्थानांतरण, पदावनति और चरित्र-हत्या के माध्यम से शांत-शिथिल किया जा रहा है।

(ix) कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यवसायियों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सम्बंधित गुप्त सूचनाओं के '*डोजियरों*' का एकत्रीकरण एवं संयोजन करना प्रारंभ कर दिया है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उजागर करके उन्हें हानि-क्षति पहुँचाई जा सकती है।

(x) पिछली काँग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काँग्रेस के नेताओं को सभी प्रकार के आयोगों, जाँचों और उनके विरुद्ध तफ़तीशें कराने की धमकियाँ दी जा रही हैं और काँग्रेस के कुछ नेताओं के विरुद्ध धमकियों का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने श्रमिकों, कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों को हर मोहल्ले और गली में कम्युनिस्ट पार्टी की कोशिकाओं के रूप में संगठित कर रही है, जो भविष्य में मोहल्ला समितियों और आतंकवादी दस्तों का केंद्र बनेंगी।

(xi) कानून (विधि) और व्यवस्था से सम्बंधित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों की तर्ज पर कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बंधित स्थानीय लोगों को भी व्यवस्थित रूप से उपद्रवी गतिविधियों, अराजकता और झगड़ों को नियोजित करने के लिए राज-सत्ता द्वारा असंवेधानिक शक्तियाँ प्रदत्त की जा रहीं हैं। इससे जनमानस के मध्य कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है और भारत के संविधान और विधि द्वारा स्थापित प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल गिरा कर कम्युनिस्ट पार्टी अपना दोहरा उद्देश्य पूरा कर रही है।

(xii) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसानों द्वारा उनके अपने खेतों की उपज के संचय के अधिकार को समाप्त करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बंधित स्थानीय लोगों की समितियाँ बनाई जा रहीं हैं, जिन्हें गण समितियाँ कहा जाता है। वस्तुत: ये समितियाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सत्ता के '*लीवर*' और समानांतर सरकार के अंगों के रूप में कार्य कर रहीं हैं।

(xiii) सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों से पूर्व आपराधिक इतिहास तथा राजनीतिक-वैचारिक संबद्धता से सम्बंधित सभी जाँचों के प्रावधान ख़त्म कर दिए गए हैं। हर सरकारी विभाग में कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय आपराधिक क़िस्म के कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया जा रहा है।

(xiv) लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों की आड़ में सरकारी कर्मचारियों को पूर्व-नियोजित तरीके से एवं जानबूझकर राजद्रोही, निष्ठाहीन और अनुशासनहीन बनाया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार अपने प्रशासनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी सरकारी मशीनरी को प्रभावी ढ़ंग से नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ है। वस्तुत: कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के सरकार एवं सरकारी उपक्रमों में बढ़ते हुए प्रभुत्व के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों पर अपना नियंत्रण खो दिया है।

(xv) कम्युनिस्ट पार्टी के आपराधिक क़िस्म के कार्यकर्ताओं को निचले-कनिष्ठ स्तर की पुलिस में सम्मिलित करके और उन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पिटाई करा कर अथवा उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धमका कर, पुलिस प्रशासन में अनुशासनहीनता एवं अराजकता फैलाई जा रही है।

(xvi) कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान में बंगाली और अन्य भाषाओं में कई पत्रिकाएँ, '*जर्नल*' और दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित कर रही है। इन्हें

सड़कों की नुक्कड़ों पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं, फुटपाथ पर फेरीवालों और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है।

(xvii) सांस्कृतिक मोर्चे पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता—नुक्कड़ नाटक, ग्रामीण '*थिएटर*' और सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रकार वे कम्युनिस्ट पार्टी के नारों-उद्घोषों तथा विचारधाराओं को प्रभावी ढंग से व्यापक जनता तक पहुँचा रहे हैं।

(xviii) वामपंथी अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों, सरकारी अभियोजकों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य में विधि-कानून कार्य-धंधों में विद्यमान कम्युनिस्ट लॉबी के माध्यम से कम्युनिस्टों द्वारा न्यायपालिका में प्रवेश कर के वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(xix) व्यापारियों से हफ़्ता-फिरौती एकत्रित करके, सरकारी संरक्षण की एवज में घूस प्राप्त करके तथा निश्चित रूप से गुप्त विदेशी स्रोतों से अकूत धन-सम्पदा प्राप्त करके कम्युनिस्ट पार्टी अपने कोष एवं धन-संग्रह में सतत रूप से वृहत्तर वर्धित वृद्धि कर रही है।

12. यह संगठित सामाजिक गतिविधियों के संपूर्ण-वृहद् दायरे में कार्यरत एक शक्तिशाली बहु-आयामी प्रयास है और हर गुजरते दिन के साथ यह वर्धित द्रुतगति से क्रियाशील हो रहा है। हालाँकि कुछ बाह्य दुष्परिणाम पहले से ही परिलक्षित हो रहे हैं, परन्तु सामान्य जनमानस के जन, सतत रूप से परिवर्तित हो रहे इन परिदृष्यों के भयावह दुष्प्रभावों के विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट छल-कपट और धोखा देने में, छद्मवेश धारण करने में और दोमुँही बातें करने में माहिर हैं। इन कारणों से

इतर, सामान्य जनमानस की उदासीन-सुस्त प्रतिक्रिया के कुछ अन्य कारण भी हैं। जबकि सामान्य जनमानस के जन, कम्युनिस्टों द्वारा नित्य घेराव को लेकर कुछ हद तक उत्तेजित-आक्रोशित हैं, परन्तु कम्युनिस्टों की घेराव पद्धति उनके विराट नृशंस बाह्य रूप में से केवल एक को सीमित अर्थों में प्रस्तुत करती है और कम्युनिस्टों की घेराव पद्धति किसी भी तरह से उनकी अन्य पद्धतियों की तुलना में सर्वाधिक भयावह नहीं है। सामान्य जनमानस का जन आज भी और अभी तक कम्युनिस्टों की सरकारी नीतियों के द्वारा अपने महत्त्वपूर्ण हितों पर किसी अन्य दुष्प्रभाव का संज्ञान लेने में सर्वथा असमर्थ है। अत: सामान्य जनमानस वर्तमान व्यवस्था को एक प्रकार की सतही एवं अल्पकालिक उथल-पुथल के रूप में चिह्नित कर रहे हैं। कम्युनिस्टों की सरकारी नीतियों के द्वारा सामान्य जनमानस के लोकतांत्रिक, स्वातंत्र्य तथा संपत्ति सम्बंधित हितों पर सुनियोजित तरीके से हमला करने की प्रवृत्ति से आम-जन अनभिज्ञ हैं। सामान्य जनमानस के अवचेतन मन में अभी भी आशा की एक किरण है कि काँग्रेस पार्टी उचित समय पर इस बहुदलीय गठबंधन को उखाड़कर सत्ता में वापस आएगी। इस दिवास्वप्न मृगमरीचिका विचार से बंगाल के सामान्य जनमानस को बहुत राहत मिलती है कि काँग्रेस की केंद्र सरकार सदैव उपयुक्त समय पर हस्तक्षेप कर सकती है।

13. ये मोहक भ्रम और आशाओं से अधिक कुछ नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के भद्र जन, प्रलय और रक्त-स्नान के साक्षी बनने के मार्ग पर सतत रूप से अग्रसर हो रहे हैं। उनकी विकट परीक्षा की अवधि के दौरान उनकी उक्त परीक्षा में सफलता में ही उनके अस्तित्व की रक्षा निहित है। परन्तु यह उनके आंतरिक जीवन में इस दुविधा से युक्त पक्षाघात का प्रतिकार करने के उनके स्वयं के सक्रिय प्रयासों पर निर्भर करेगी। यद्यपि दो बातें सर्वथा

निश्चित हैं: (1) कि स्थितियाँ सतत रूप से गंभीर उथल-पुथल की ओर इशारा कर रही हैं और (2) कि, अंतिम विश्लेषण एवं निष्कर्षों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के लोगों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, हालाँकि उन्हें शेष भारत से तात्कालिक रूप से अविलंब सहयोग-समर्थन की आवश्यकता है।

14. कम्युनिस्ट पार्टी को कोई भ्रम नहीं हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि संयुक्त मोर्चे की मिली-जुली सरकार दीर्घ समय तक यथावत नहीं रहेगी। 'यूनाइटेड फ्रंट (यूएफ)' का अल्प-शासनकाल, कम्युनिस्ट पार्टी की दृष्टि में एक सर्वोत्तम संक्रमणकालीन एवं अनुकूल व्यवस्था है और इसे वे अपनी नियोजित क्रांति के अगले और उच्च चरण के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। बंगाल के जन-मानस, जो वर्तमान व्यवस्थाओं की अशक्त-निर्बल स्थिति से राहत पाना चाहते हैं और जो वर्तमान संयुक्त मोर्चे की मिली-जुली सरकार के पदच्युत होने की राह देख रहे हैं, निस्संदेह उनको इसके पश्चात् के घटनाक्रमों से मानसिक सदमा मिलेगा, इसकी संभावना अत्यधिक प्रबल है।

15. कम्युनिस्ट पार्टी एक निर्णायक वर्ग-युद्ध को लेकर उत्सुक है और केवल सामरिक कारणों से अपने कार्यकर्ताओं की नृशंसता को नियंत्रण में रख रही है। कम्युनिस्ट पार्टी जब संयुक्त मोर्चे के मंत्रिस्तरीय गठबंधन के विखंडन के समय का चयन करेगी, तब वह पश्चिम बंगाल राज्य की काँग्रेस, पीएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी पार्टियों पर दोष मढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। कम्युनिस्ट पार्टी, भ्रम का मकड़जाल बुनकर स्वयं को जन-मानस के हितों की एकमात्र रक्षक होने का दावा करेगी। यदि पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं

को जन-मानस के हितों की रक्षा करते हुए शहीद करने का नाटक करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के नारों-उद्घोषों की द्वंद्वात्मक प्रकृति और उसकी रणनीति में लचीलापन उसे किसी भी स्थिति में उपयुक्त रुख अपनाने में सक्षम बनाता है।

16. कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार क्रांति का अगला चरण प्रारंभ करने का समय आ गया है। चूँकि काँग्रेस पार्टी के द्वारा बहुमत की सरकार बनाने या शासन की अनुमति प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है, अतः पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना तय है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के पश्चात् छह महीने के भीतर विधानसभा के जन-प्रतिनिधि सदस्यों के निर्वाचन हेतु नए चुनाव होने चाहिए। यह वह निर्णायक दिन होगा जिसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी अपने उग्र जन-आंदोलनों के माध्यम से सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर स्वयं को युद्ध के लिए तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में विद्यमान राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन यह सुनिश्चित करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में यदि मध्यावधि विधानसभा के चुनाव आहूत होते है तो वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी अकेले अपने दम पर विजयी हो सकती है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जन-मानस में संचरण कर रहे तथा जन-मानस में वर्धित हो रहे भारी असंतोष और विद्रोह की ज्वाला से अवश्यमेव लाभान्वित होगी। यह सर्वथा निश्चित है कि पश्चिम बंगाल राज्य के मध्यावधि विधानसभा के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को वर्धित असंतोष और विद्रोह की भावनाओं से अवश्यमेव सहयोग प्राप्त होगा, जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अल्पकालिक शासन के दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जानबूझकर एवं सुनियोजित तरीके से भड़काया एवं

प्रज्ज्वलित किया है। हाल ही में पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में हुए नगर निगम के चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी को मिली भारी जीत से भविष्य में घटित होने वाली स्थिति का संकेत हमें पहले ही मिल चुका है।

17. वर्तमान के संयुक्त मोर्चे के शासन के विपरीत 'पीपुल्स गवर्नमेंट' में केवल कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सम्मिलित होंगे। जब वे अस्तित्व में आएँगे तो यह वर्तमान संयुक्त मोर्चे के शासन से बहुत पृथक होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी को तब अपनी कुत्सित गतिविधियों या अपनी अमानवीय मंशाओं को छुपा कर कार्य करना नहीं पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा संचालन, आंदोलन और संगठनों के माध्यम से एक ठोस जन आधार तैयार करने तथा वृहत्तर आंदोलन के लिए वर्ग युद्ध के अंगों और शासन के लिए समानांतर अंगों का निर्माण करने के पश्चात् निस्संदेह कम्युनिस्ट पार्टी वस्तुत: पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पश्चिम बंगाल राज्य और बंगाली समाज के ''वर्ग'' चरित्र को खुलेआम परिवर्तित करने के लिए प्रयास कर सकती है। इस नृशंस रक्तिम अमानवीय कुकृत्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय संविधान की तथा केंद्र सरकार के निर्देशों की प्रत्यक्ष अवज्ञा एवं अवमानना कर सकती है। इस चरण में कम्युनिस्ट पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करने या व्यापारिक घरानों पर व्यापक छापे मारने या उन लोगों पर लगातार दबाव बनाने में संकोच नहीं करेगी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, आधिकारिक शक्तियों के अमानवीय नृशंसता के साथ संयोजन से अभिप्रेरित बल-प्रयोग के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि वह अपने वैचारिक विरोधियों को पूर्वी पाकिस्तान या बर्मा के '*पैटर्न*' पर पश्चिम बंगाल राज्य से बाहर खदेड़ दे अथवा उन्हें विस्थापित होने के लिए विवश कर दे।

18. क्रान्ति के इस चरण में तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कम्युनिस्ट पार्टी के सशस्त्र गुटों के हिंसक विद्रोहों एवं वारदातों में सक्रिय होने की सम्भावना प्रबल है। पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रत्यक्ष शिविर और विद्यालय स्थापित किए जाएँगे और अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से हथियारों की तस्करी के लिए चीन के साथ गुप्त संपर्क स्थापित किया जाएगा। भारत के अंतरराष्ट्रीय विरोधियों द्वारा प्रदत्त एवं समर्थित ''सुरक्षित पृष्ठ भाग'' तब पूर्ण सामर्थ्य एवं उर्जा के साथ क्रियाशील होगा, जो न केवल वांछित अपराधियों को अभयारण्य प्रदान करेगा वरन् सशस्त्र आक्रमण, सशस्त्र सहायता, जासूसों की आवाजाही तथा खुफिया और प्रचार नेटवर्क के संगठन के संचालन के आधार के रूप में भी कार्य करेगा। असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नेफा के साथ भारत के अशक्त-निर्बल संबंधों को और अधिक छिन्न-भिन्न कर, उन्हें भौगोलिक रूप से भारत से पृथक कर तथा भारत के इन भागों को भारत के अन्य भागों से पूर्ण रूप से अर्थात् सांस्कृतिक-आर्थिक-सामजिक-राजनीतिक-प्रशासनिक रूप से पृथक करने का प्रयास किया जाएगा। पूर्वी भारत के अन्य संकटग्रस्त स्थानों और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार सक्रिय एवं क्रियाशील भारत-विरोधियों के साथ उनके द्वारा समन्वय स्थापित करने के सतत प्रयास, इस संभावना को अधिक बल देते हैं कि यह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा देखा जा रहा महज एक दिवास्वप्न नहीं है।

19. ऐसा न हो कि हम यह आशा करने में लग जाएँ कि इस सशस्त्र विद्रोह को केंद्र सरकार के आदेश पर भारतीय सेना के हस्तक्षेप से त्वरित ही कुचला जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि इन नृशंस कम्युनिस्टों के द्वारा भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में प्रारम्भ किए गए गृह-युद्धों में केंद्र की दंडात्मक

कार्रवाई लगभग निरर्थक-प्रभावहीन ही प्रमाणित हुई है अथवा कम्युनिस्टों की गुरिल्ला युद्ध-रणनीति के विरुद्ध सीमित प्रभावशीलता के परिणामस्वरूप राष्ट्र को अत्यधिक हानि हुई है। निस्संदेह कम्युनिस्टों के द्वारा भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में प्रारम्भ किए गए गृह-युद्धों के इतिहास को शिक्षाप्रद मानकर संज्ञान लेने से हमें लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। कम्युनिस्टों द्वारा केंद्रीय बलों को आक्रमण करने वाली विदेशी सेना के रूप में निरूपित किया जाएगा और उन्हें कम्युनिस्टों की गुरिल्ला रणनीति के उपयोग के द्वारा रक्षात्मक होने के लिए विवश किया जाएगा। कम्युनिस्ट, स्वतंत्रता का राग-आलाप करके संचार सेवाओं को बाधित करेंगे, रेलवे ट्रैक को उखाड़ेंगे, केंद्र सरकार के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर बलात् अधिकार स्थापित करेंगे, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लूटेंगे तथा पश्चिम बंगाल राज्य में दीर्घकालिक व्यापक आम-हड़तालों के माध्यम से जन-समुदाय के जीवन को पूरी तरह से ठप करने का प्रयास करेंगे। यदि भारतीय सेना, मिज़ो हिल्स या नागालैंड जैसे छोटे अविकसित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में तथा क़ानून-व्यवस्था के अनुरक्षण में आज असमर्थ एवं हतोत्साहित हो रही है, तो उस भारतीय सेना से घनी आबादी वाले पश्चिम बंगाल राज्य में बड़े पैमाने पर गोलीबारी और हत्याओं के बिना शांति स्थापित करने की आशा करना दिवास्वप्न देखने के समान ही होगा।

20. यदि ऐसा ही सब-कुछ चलता रहा तो पश्चिम बंगाल में घटनाएँ स्वतंत्र रूप से या पृथक-पृथक भाव से घटित नहीं होंगी। पश्चिम बंगाल में तोड़फोड़ की घटनाएँ, भारत के अन्य भागों में भी भारत विरोधियों को तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित करेंगी। क्योंकि साम्यवाद का वृहद् लक्ष्य उत्तर-पूर्व भारत पर एकाधिपत्य स्थापित करने का नहीं है वरन् उसका लक्ष्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर एकाधिपत्य

स्थापित करने का है। पश्चिम बंगाल केवल एक सामुद्रिक-रणनीतिक क्षेत्र तथा एक *स्प्रिंगबोर्ड* की भाँति है, जिसका उपयोग करके साम्यवादी एकजुटता और नृशंस आक्रामकता को भारतीय उपमहाद्वीप में धार दी जाएगी।

जिस कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाने में सक्रिय हैं उन्हीं के भारतीय संसद में सदस्य हमारी केंद्र सरकार पर भी संसद के भीतर से लगातार दबाव बनाने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान सत्ता-संतुलन में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्र में भी कम्युनिस्ट पार्टी, काँग्रेस के साथ या काँग्रेस के बिना भी अन्यान्य प्रकार की ''यूनाइटेड फ्रंट (यूएफ)'' सरीखी सरकार बनाए, जिसमें कम्युनिस्टों के महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व घटक होने की सम्भावना प्रबल है। इसके अतिरिक्त, जो शक्तियाँ पश्चिम बंगाल में दबाव, नारों-उद्घोषों और भ्रम का मकड़जाल बनाने में संलग्न हैं, वे शेष भारत में भी और भी बड़े पैमाने पर भारतीय समाज को विखंडित करने का कुकृत्य कर रहीं हैं। अत: जब तक कुछ नए कारक जन्म नहीं लेते हैं या कुछ नए सार्थक प्रयास समय रहते हुए नहीं किए जाएँगे तब तक इस विमर्श में इंगित कु-परिणाम एक निश्चित समय-अंतराल के पश्चात् अवश्य घटित होंगे।

21. इस समय, राजनीतिक उद्भव की यह प्रक्रिया अपरिहार्य-सी प्रतीत हो रही है। आज पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधियों की शक्ति तीव्रता से क्षीण हो चुकी है, वस्तुत: वे सभी राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के कुकृत्यों का सार्थक विरोध करने में सर्वथा असक्षम हो चुके हैं। वस्तुत: काँग्रेसियों में कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने की भावना भी न्यूनतम हो चुकी है। काँग्रेसियों का आत्मविश्वास क्षीण तथा समाप्त-सा हो गया है और काँग्रेसियों का नेतृत्व भ्रमित तथा पंगु-सा हो गया है। काँग्रेसियों ने कम्युनिस्ट

पार्टी के लिए निष्पक्ष एवं विधिवत रूप से *सैपर्स और माइनर्स*[6] की भूमिका निभाई है। अत: भविष्य में बांग्ला काँग्रेस को किसी भी रूप में संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित होने का सुअवसर मिलने की सम्भावना कम तथा न्यूनतम है। ग़ैर-कम्युनिस्ट पार्टियों में न केवल काँग्रेस के प्रति वरन् एक-दूसरे के प्रति भी बहुत अधिक अविश्वास और रिपु-भाव है। ये राजनीतिक दल, कम्युनिस्टों के क्रांतिकारी नारों-उद्घोषों से भ्रमित-पंगु और सम्मोहित हो गए हैं, जो पश्चिम बंगाल के भीतर कम्युनिस्ट पार्टी की संगठित राजनीतिक गतिविधियों की दिशा-दशा और गति तय कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा में कार्य लगभग ठप्प-सा हो गया है, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा नित्य-निरंतर विधानसभा को बाधित किया जा रहा है, अत: कम्युनिस्ट पार्टी की इस आतंकी रणनीति के दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा में भारत समर्थक सदस्य लगभग पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए हैं। ऐसा अधिकाधिक रूप से प्रतीत हो रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य का समाज जीर्ण-शीर्ण मरणासन्न होकर मानो इच्छा-मृत्यु का आग्रह कर रहा है।

22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिस्थितयाँ संभावित रूप से बहुत संकटजनक-भयावह हो चुकी हैं। वस्तुनिष्ठ कारण एवं नित्य घटित हो रहे घटनाक्रमों से सम्बंधित साक्ष्य ऐसे-ही आशंकाप्रद गंभीर पूर्वानुमानों को बल दे रहे हैं। वस्तुत: पश्चिम बंगाल राज्य में नव-क्रांति के नाम पर भारत का विध्वंस करने के लिए ज्वाला को प्रज्ज्वलित किया जा चुका है और नक्सलबाड़ी, भावी वृहद्-व्यापक रक्तिम क्रांति की एक '*ड्रेस रिहर्सल*' मात्र

[6] *अनुवादक की टिप्पणी—सैपर्स और माइनर्स,* सैन्य इंजीनियरों के दो पृथक-पृथक समूह होते हैं। *सैपर्स* : ये इंजीनियर खाइयों या '*सैप*' का प्रयोग करके दुश्मन की किलेबंदी को नष्ट करते हैं। *माइनर्स* : ये इंजीनियर, युद्ध भूमि में सुरंग का निर्माण कर दुश्मनों को क्षति पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

है। हालाँकि लोकतांत्रिक उद्देश्यों एवं पद्धतियों की गरिमा को पुन: बहाल किया जा सकता है। प्रत्येक स्वस्थ जीव, अपने जीवनकाल में गंभीर रुग्णता-व्याधि का सामना करता है, यद्यपि रोग को एँटी-बॉडीज़ द्वारा पलटवार की प्रक्रिया के माध्यम से ठीक किया जाता है, जो हमलावर रोगाणुओं को पृथक करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इसी प्रकार, एक सामाजिक जीव में आत्मरक्षा और प्रतिकार के अंग निहित होते हैं, जो असामाजिक तत्वों को अलग-थलग करके नष्ट कर सकते हैं।

23. इस समय ग़ैर-कम्युनिस्ट शक्तियाँ हतोत्साहित, विभाजित और भ्रमित हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में आसन्न विपदा के विरोध की एक धुंधली-सी झलक तथा अल्प जागरूकता भी दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में कम्युनिस्टों द्वारा प्रज्ज्वलित ज्वाला से उपजने वाली आसन्न विपदा के प्रति जागरूकता को जागृत तथा सुदृढ़ करना होगा और कम्युनिस्ट पार्टी की छल-कपट एवं झूठ का मकड़जाल सृजित करने की प्रकृति को पश्चिम बंगाल राज्य के जन-मानस के समक्ष उद्धृत करना होगा। आख़िरकार, कम्युनिस्ट पार्टी का पृष्ठवंश एवं रीढ़ की हड्डी खंडित है और वस्तुत: कम्युनिस्ट पार्टी एक कागज़ी शेर है। इतिहास साक्षी है कि कम्युनिस्ट पार्टी के असंख्य वचन-वादे झूठे और छल-प्रपंच प्रमाणित हुए हैं। इन सभी तथ्यों को जन-मानस के समक्ष सुनियोजित प्रकार से प्रस्तुत करके कम्युनिस्ट पार्टी को ऐतिहासिक रूप से शांत-शिथिल कराया जा सकता है। कई दशकों के अंतराल में कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वयं को समाज के लिए एक प्रकार का नैतिक कोढ़ी बना लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी वस्तुत: विपुल प्रचार-प्रसार और निरंतर संगठनात्मक गतिविधि के माध्यम से ही अपनी समाज के समक्ष एक लोकप्रिय छवि प्रस्तुत करने में सफल होती है। यदि हम सामूहिक रूप से दृढ़ प्रयास करेंगे तो हम कम्युनिस्ट पार्टी के खोखले

दिखावे, छल-प्रपंच तथा झूठ के मकड़जाल को आसानी से समाज के समक्ष उद्धृत कर सकते हैं। हमें सात लीग जूतों[7] को पहनकर कूच-प्रयाण करते आठ फुट लंबे कम्युनिस्टों को भविष्य की लहर के रूप में चिह्नित करने से परहेज़ करना होगा। भविष्य में साम्यवाद का आधिपत्य सम्पूर्ण विश्व पर स्थापित होगा यह एक कपोल-कल्पित मिथक है और अत: देशभक्त शक्तियों को कम्युनिस्टों से भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है।

24. यह स्मरण रखना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी सभी स्तरों पर और सभी रूपों में सत्ता पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती है। अंत: कम्युनिस्ट पार्टी का संघर्ष नृशंसता से अभिप्रेरित विचारों का समूह है तथा इसकी प्रकृति और दायरा कुछ इस प्रकार का है कि यह अपने विरोधी विचारों के किंचित् मात्र अस्तित्व के भी विरुद्ध है। कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य किसी भी स्थान या राज्य या राष्ट्र में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सैन्य एकाधिकार प्राप्त करने तक सतत संघर्ष करने का है। अत: कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों एवं पद्धतियों में प्रभावी नृशंसता से अभिप्रेरित आक्रामक रणनीतियाँ अंतर्निहित हैं। कम्युनिस्ट कोई साधारण अपराधी नहीं हैं, जिन्हें कानून और व्यवस्था की शक्तियों का प्रयोग करके रोका जा सके। वस्तुत: कम्युनिस्ट अपनी तरह की तथाकथित सामाजिक

---

[7] *अनुवादक की टिप्पणी*—'सात-लीग जूते' यूरोपीय लोककथाओं में एक जादुई-तिलस्मी तत्त्व है। एक '*लीग*' की दूरी भूमि पर तीन मील या 4.83 किलोमीटर के बराबर होती है। एक '*लीग*' की दूरी समुद्री सतह पर तीन नॉटिकल मील या 5.55 किलोमीटर के बराबर होती है। इस चमत्कारी जूते को पहनकर चलने वाला व्यक्ति, भूमि पर चमत्कारिक रूप से एक कदम में सात '*लीग*' अर्थात् 9 मील या 43.47 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वह बहुत तीव्र गति से चलने में समर्थ होता है। यूरोपीय दन्तकथाओं में एक जादुई चरित्र, कथा के मुख्य नायक को किसी विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए यह चमत्कारी जूते देता है।

क्रांति के सक्रिय नृशंस एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं। अत: कम्युनिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई के एक प्रभावी कार्यक्रम में तत्काल विपदा से निपटने के लिए कुछ अल्पकालिक उपायों के साथ-साथ कुछ दीर्घकालिक उपायों के रूप में सामाजिक न्याय, वैचारिक एवं संगठनात्मक युद्ध के सुनियोजित क्रियान्वयन की महती आवश्यकता है।

25. कम्युनिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई के एक सुनियोजित प्रभावी कार्यक्रम के कुछ तात्कालिक और भावी तत्त्वों को संक्षेप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सत्ताधारी 'संयुक्त मोर्चे' के लोकतांत्रिक घटकों को यह आत्मअनुभव-एहसास कराया जाना चाहिए कि कम्युनिस्टों को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पर हावी होने की अनुमति देकर, वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आधार स्तंभों को नष्ट कर रहे हैं। इन लोकतांत्रिक दलों को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के भीतर रहते हुए कम्युनिस्टों की नृशंस विचारधारा का पुर-जोर विरोध करना चाहिए, भले ही इसके परिणामस्वरूप उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की बैसाखी पर चलने वाली गठबंधन की सरकार अल्पमत क्यों न हो जाए। हर स्थिति में, इन लोकतांत्रिक दलों के सत्ता से चिपके रहने के स्वार्थपरक प्रयास न केवल अल्पावधि में निरर्थक प्रमाणित होंगे, वरन् दीर्घावधि में अत्यधिक आत्मघाती भी होंगे।

(ii) अब समय आ गया है जब इन लोकतांत्रिक दलों को काँग्रेस के प्रति अपनी अंधी घृणा का त्याग करना चाहिए और साम्यवाद के विरोधी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। यदि ये लोकतांत्रिक पार्टियाँ एक साझा कार्यक्रम के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाकर समन्वय सकती हैं, तो साम्यवाद का विरोध करने के लिए

एक साझा कार्यक्रम के अंतर्गत उन लोकतांत्रिक पार्टियाँ के पास कॉंग्रेस और अन्य ग़ैर-कम्युनिस्ट शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर समन्वय करने का कहीं अधिक बड़ा कारण है।

(iii) कॉंग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल के भीतर और विधानमंडल के बाहर, स्वयं को सुव्यवस्थित करना होगा। फिलहाल कॉंग्रेस पार्टी केवल चुनावी रणनीति बनाने में और वोट प्राप्त करने में ही माहिर है। कॉंग्रेस पार्टी को फ़ौरी-तौर पर उन सक्षम लोगों से सहयोग लेना चाहिए, जो सार्वजनिक मुद्दों की वास्तविक पृष्ठभूमि पर समुचित जानकारी प्रदान करने में सक्षम हैं। लोकतांत्रिक विषयों को लोकतंत्र के पक्ष में और साम्यवाद के विरुद्ध प्रलेखित किया जाना चाहिए। कम्युनिस्ट सरकार के कुकर्मों को जन-मानस के समक्ष प्रकट तथा प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी के नापाक मंसूबों को उजागर करना चाहिए। लोकतांत्रिक पार्टियों को अपने वैचारिक सदस्यों में से सक्षम-जुझारू तर्क-वितर्क करने वाले प्रखर वक्ताओं को प्रमुखता देनी चाहिए। लोकतांत्रिक पार्टियों को कम्युनिस्ट पार्टी के नापाक मंसूबों को उजागर करने वाले संदेशों के साथ सड़कों पर उतरना चाहिए तथा गांवों में और कस्बों में घर-घर जाकर आम जन को जागृत करना चाहिए।

(iv) हालाँकि भारत में प्रेस का स्वामित्व अभी भी ग़ैर-कम्युनिस्टों के पास है, यद्यपि इसमें कम्युनिस्ट समर्थक अथवा कम्युनिस्टों से सहानुभूति रखने वाले पत्रकारों और विचारकों ने भारी घुसपैठ कर ली है। '*प्रेस रिपोर्टिंग*' के तौर-तरीके पर भी गौर किया जाना चाहिए और कम्युनिस्ट प्रभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि कम्युनिस्टों द्वारा सत्ता पर एकाधिकार स्थापित करने के विषय में वस्तुतः कुछ भी प्रगतिशील या महान नहीं है।

(v) देश के भीतर की प्रेस-मीडिया को पश्चिम बंगाल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की विध्वंसक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर एकमत होकर तथा बिना भयग्रस्त हुए, पूरी तरह से प्रकाश डालना चाहिए।

(vi) काँग्रेस और अन्य लोकतांत्रिक पार्टियाँ जैसे स्वतंत्र पार्टी[8], भारतीय जनसंघ[9], पी.एस.पी.[10], डी.एम.के. आदि से संबंधित ग़ैर-

---

[8] *अनुवादक की टिप्पणी*—स्वतन्त्र पार्टी, भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अगस्त, 1959 में की थी। इस राजनीतिक दल ने जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति का विरोध किया था और तथाकथित ''लाइसेंस-परमिट राज'' को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों के परिणामस्वरूप दुर्भाग्य से इसकी जमींदारी और उद्योगपतियों की हितैषी पार्टी के रूप में ब्रांडिंग की गई। स्वतन्त्र पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की थी; परन्तु 1974 सीई में पीलू मोदी की अध्यक्षता वाली इस पार्टी ने भारतीय लोकदल में विलय कर के अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया था।

[9] *अनुवादक की टिप्पणी*—भारतीय जनसंघ, राजनीतिक दल की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 के दिन दिल्ली में की गई थी। इसके तीन संस्थापक सदस्य थे—श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। इस राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न दीपक था। इसने सन् 1952 सीई के संसदीय चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी जिसमें डाक्टर मुखर्जी स्वयं भी सम्मिलित थे।

भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल (वर्ष 1975-1976 सीई) के पश्चात् ''भारतीय जनसंघ'' सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने परस्पर विलय करके एक नए दल ''जनता पार्टी'' का गठन किया था। आपातकाल से पूर्व बिहार विधानसभा में ''भारतीय जनसंघ'' के विधायक दल के नेता लालमुनि चौबे ने ...

[10] *अनुवादक की टिप्पणी*—''प्रजा सोशलिस्ट पार्टी'' (पी.एस.पी.) भारत का एक राजनीतिक दल था। यह राजनीतिक पार्टी सन् 1952 सीई में बनी थी और सन् 1972 सीई तक अस्तित्व में रही। इसका जन्म ''*सोशलिस्ट पार्टी*'' एवं किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणामस्वरूप हुआ था। ''*सोशलिस्ट पार्टी*'' के संस्थापक नेता जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, बसावन सिंह थे तथा ''किसान मजदूर प्रजा पार्टी'' के संस्थापक नेता जे.बी. कृपलानी थे।

कम्युनिस्ट सांसदों को नियमित रूप से पश्चिम बंगाल राज्य का दौरा करना चाहिए। उन्हें अपने संबंधित राज्यों तथा भारत की संसद में अपने अध्ययन और *रिपोर्टों* को प्रस्तुत करके जन-मानस एवं राष्ट्र को कम्युनिस्ट पार्टी के कुकृत्यों के विरुद्ध जागृत करना चाहिए।

(vii) ग़ैर-कम्युनिस्ट शिक्षकों, शिक्षाविदों, लेखकों और कलाकारों को शैक्षिक और सांस्कृतिक मोर्चों पर कम्युनिस्टों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिकार करने के लिए संगठित किया जाना चाहिए।

(viii) ग़ैर-कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों को अध्ययन और चर्चा के माध्यम से साम्यवाद के मुद्दे पर स्वयं को अकाट्य तर्क-वितर्क करने के लिए समुचित तथ्यों से सुसज्जित किया जाना चाहिए।

(ix) कम्युनिस्ट पार्टी की दबाव वाली कुटिल रणनीति से दुष्प्रभावित हुए व्यक्तियों को अल्पकालिक अज्ञातवास में जाकर मौन धारण करने अथवा कम्युनिस्ट पार्टी के समक्ष नतमस्तक होने के स्थान पर, कम्युनिस्टों का प्रभावी ढ़ंग से प्रतिकार करना चाहिए।

...जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के समर्थन में बिहार विधानसभा से अपना त्यागपत्र दे दिया। सन् 1980 सीई में "जनता पार्टी" विखंडित हो गई। "जनता पार्टी" में "भारतीय जनसंघ" के एक गुट ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवानी के नेतृत्व में "भारतीय जनसंघ" से पृथक होकर "समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा" के नेताओं के साथ मिलकर, "भारतीय जनता पार्टी" का गठन किया। उसके पश्चात "भारतीय जनसंघ" के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर बलराज मधोक ने "अखिल भारतीय जनसंघ" को चुनाव आयोग से पंजीकरण कराकर "भारतीय जनसंघ" को यथावत बनाए रखा। प्रोफेसर बलराज मधोक सन् 2016 सीइ तक "अखिल भारतीय जनसंघ" के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। प्रोफेसर बलराज मधोक की मृत्यु के पश्चात् "अखिल भारतीय जनसंघ" के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. आचार्य भारतभूषण पाण्डेय हैं। अखिल भारतीय जनसंघ की कथित विचारधारा "एकात्म मानववाद" सर्वप्रथम सन् 1965 सीई में दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी।

(x) नियोक्ताओं को कम्युनिस्ट पार्टी की आतंकी रणनीतियों के विरुद्ध ठोस उद्योग-व्यापी समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी की नृशंसता के विरुद्ध नियोक्ताओं को उद्योग-वार तालाबंदी तथा एक औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना करनी चाहिए। नियोक्ताओं को सभी मंचों से कम्युनिस्ट पार्टी की नृशंसता के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की माँग करनी चाहिए।

(xi) पुलिस प्रशासन एवं पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों के वैध निर्वहन में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण अथवा हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन एवं पुलिसकर्मियों को अपनी शिकायतों-अवसादों को मुखरता से उच्चस्थ अधिकारियों एवं नीति-निर्धारकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और सभी संवैधानिक उपायों का उपयोग करके उन समस्याओं का त्वरित निवारण करवाना चाहिए। पुलिस प्रशासन एवं पुलिसकर्मियों को कानून का पालन करने वाले और विचारशील नागरिकों का सक्रिय समर्थन प्राप्त करना चाहिए। विचारशील नागरिकों का यह कर्तव्य है कि इन अपरिहार्य विकट परिस्थितियों में वे पुलिस प्रशासन एवं पुलिसकर्मियों को उपयुक्त सुरक्षा एवं तर्कसंगत समर्थन प्रदान करें।

26. सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के कंधों पर है। भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखना भी केंद्र सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार द्वारा कानून से सम्बंधित दायित्वों का निर्वहन वस्तुत: हिमखंड की नोक के समान है। केंद्र सरकार के कंधों पर भारत की एकता-अखंडता, सुरक्षा तथा भारत में स्वतंत्रता का वातावरण यथावत बनाए रखने की भी ज़िम्मेदारी है। अपनी वर्तमान अशक्त-निर्बल स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा रक्षात्मक नीति के अनुपालन से कम्युनिस्टों को वृहत्तर स्तर

पर आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठने तथा स्वयं को राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए कुशलतापूर्वक कार्य न करने की प्रवृत्ति अथवा लेशमात्र भी कठोर निर्णय नहीं लेने की नीति के फलस्वरूप कालांतर में कम्युनिस्ट पार्टी और अधिक सशक्त होगी तथा केंद्र सरकार का यह ग़ैर-ज़िम्मेदाराना रवैया कम्युनिस्ट पार्टी को वर्धित नृशंसता के लिए प्रोत्साहित करेगा। केंद्र सरकार को अपनी निष्क्रियता के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो रही विपदा को समय रहते ही स्पष्ट रूप से समझना होगा, इससे पहले कि स्थिति और अधिक विकट-भयावह हो जाए। उस अनिश्चितता एवं संकटजनक परिस्थिति में उपचारात्मक कार्रवाई का क्रियान्वयन करने में अत्यधिक विलम्ब करना उचित नहीं है।

27. स्पष्ट रूप से एवं स्पष्ट शब्दों में कहें तो, केंद्र सरकार की कार्रवाई में गृह मंत्रालय द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति की सतत रूप से निगरानी करना, केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में सख्त अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ सामान्य-व्यावहारिक संबंध स्थापित करना तथा सीमा सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करना सम्मिलित है। केंद्र सरकार के मंत्रियों और उच्चस्थ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल राज्य के नियमित दौरे करने चाहिए तथा उन प्रशासनिक बलों के साथ बैठकें एवं चर्चा करनी चाहिए जो इन कठिन परिस्थितियों में भी संविधान को बचाए रखने के लिए पुर-जोर प्रयत्न कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों और उच्चस्थ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में कार्यरत प्रशासनिक बलों को सुदृढ़ और पुनर्जीवित करना चाहिए तथा प्रशासनिक एवं नागरिक सेवाकर्मियों के मनोबल को गिरने से रोकने का यथासम्भव प्रयास करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी को रेलवे, डाक और तार, बंदरगाह, गोदी और हवाई अड्डे आदि जैसे केंद्रीय सेवाओं के साथ खिलवाड़ करने अथवा उन्हें

नष्ट करने की छद्म अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। इस दिशा में केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की घेराव पद्धति की निंदा करना एक साहसिक एवं प्रशंसनीय कदम है। भारत के प्रबुद्ध जन-मानस के जीवंत जन, केंद्र सरकार से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह साम्यवादी गतिविधियों के अन्य सभी नृशंस पहलुओं पर अपनी नीतियों की घोषणा यथाशीघ्र करेगी।

28. पश्चिम बंगाल में व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी को यह आत्मअनुभव-एहसास होना चाहिए कि आज व्यवसाय का चरित्र संस्थागत है और उद्योग की समृद्धि में श्रमिकों और उपभोक्ताओं की वैध हिस्सेदारी है। अंत: वैध व्यवसाय के पुष्पित-पल्लवित होने में ही जन-मानस की सामूहिक प्रसन्नता निहित है। इस दृष्टि के अनुसार व्यवसाय वस्तुत: जन-मानस का पर्याय है। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा वैध व्यवसाय के उपक्रमों को नष्ट करना, एक प्रकार से जन-मानस के सामूहिक नरसंहार करने के समान है। उत्पादकता और आर्थिक लाभ में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगपतियों को अपने उद्योगों में प्रयुक्त तकनीक में आवश्यक सुधार करना होगा। उद्योगपतियों को यह भी देखना, समझना और सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालयों, कॉलेजों और जनमत के अंगभूतों में उनके उद्योग-व्यवसाय के विरुद्ध भावनाओं एवं तर्कों को समुचित रूप से प्रत्युत्तर दिया जा रहा है कि नहीं। उद्योगपतियों एवं उद्योगों-व्यवसायों को देश के सांस्कृतिक जीवन में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उद्योगपतियों एवं उद्योगों-व्यवसायों का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होना चाहिए, वरन् उन्हें यह भी देखना, समझना और सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियों और उनके द्वारा अर्जित लाभ से भारत के राष्ट्रीय मूल्यों तथा सत्य, सद्भाव, सेवा और स्वतंत्रता के पक्षसमर्थकों को संबल प्राप्त हो। उद्योगपतियों एवं उद्योगों-व्यवसायों को अंधेरे के पक्षसमर्थकों और आक्रामक शक्तियों के

समक्ष शांत–असहाय होकर, विनम्रतापूर्वक आत्मसमर्पण करने के स्थान पर प्रतिकार करना होगा।

29. नीति निर्माण के स्तर पर, हमारे शासकों तथा नीति–निर्धारकों को यह आत्मअनुभव–एहसास होना चाहिए कि उनकी गलत नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग अव्यवहारिक बना दिया है, जो भारत में व्यापक अशांति और असंतोष का एक मुख्य कारण है। शासकों एवं नीति–निर्धारकों को व्यवहारिक नीति का अनुपालन करना चाहिए। भारत के शासकों एवं नीति–निर्धारकों को भारतीय अर्थव्यवस्था को यथासम्भव सिद्धांतवादी नियंत्रणों और प्रतिबंधों से मुक्त करना चाहिए तथा उत्पादन एवं उत्पादकता को वर्धित करने के प्रयासों को विशेष बल एवं समर्थन देना चाहिए।

30. मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत यह विवरणों का संक्षिप्त पर फिर भी एक विस्तृत खाका है और वस्तुत: यह एक नितांत संदिग्ध प्रस्ताव भी है क्योंकि इसे महत्त्वपूर्ण मानकर वृहद् स्तर पर क्रियान्वित करना एक दुष्कर कार्य है। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकतांत्रिक शक्तियाँ अशक्त–निर्बल और जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं और अगर उन्हें उनके भाग्य के भरोसे पर छोड़ दिया जाएगा, तो इससे उनके अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि दिलचस्प पर पेचीदा तथ्य यह है कि साम्यवाद पश्चिम बंगाल राज्य में अत्यधिक सुदृढ़ हो गया है, पर फिर भी, वह भी अत्यधिक अशक्त–निर्बल है। वस्तुतः साम्यवाद, सत्य की जाँच–कसौटी के समक्ष क्षणभर भी टिक नहीं सकता है क्योंकि साम्यवाद झूठ, भय और हिंसा के वातावरण में ही फल–फूल सकता है।

31. यदि शेष भारत के जन, पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में केंद्र सरकार की नीतियों का पुर–जोर तरीके से समर्थन करते हैं, तो शक्तियों के

संतुलन को पश्चिम बंगाल राज्य के अस्तित्व की रक्षा करने के पक्ष में झुकाया जा सकता है और साम्यवाद को कृषि क्षेत्रों, कारखानों और विधायी कक्षों में पराजित किया जा सकता है। यद्‌यपि अगर हम अलग-थलग बने रहेंगे और पश्चिम बंगाल राज्य को राष्ट्रवादी शक्तियों के हाथों से निकलने देंगे, तो कालांतर में भारत के अन्य भाग भी पश्चिम बंगाल राज्य का ही अनुसरण करेंगे। पुरानी कहावत है—''बंगाल आज जो सोच रहा है, भारत वह कल सोचेगा''—संभवत: सत्य ही है। हमें कम्युनिस्टों के माध्यम से इससे भी अधिक दु:ख प्राप्त हो सकते हैं यद्‌यपि वे अनुक्रमिक *पैटर्न* को कायम रखेंगे।

32. ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में आज जो कुछ भी हो रहा है, उसके विषय में परिदृश्य पर बहुत ही कम जागरूकता है। हमारी संसद छोटी-छोटी अथवा गौण परिचर्चाओं में व्यस्त है। यह एक ऐतिहासिक-शिक्षाप्रद घटना की याद दिलाता है ''जब रोम जल रहा था, तब नीरो निरर्थक कार्यों को करने में व्यस्त था।'' दायित्वों के निर्वहन के विषय में खरे नहीं उतर पाने में विफलता, अकेले पश्चिम बंगाल राज्य की नहीं होगी, वरन् पूरे भारतवर्ष की होगी। अत: यह प्रत्येक देशभक्त राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व और समग्र रूप से राष्ट्र के प्रत्येक देशभक्त नागरिक पर निर्भर करता है कि वे जागृत होकर इस विपदा से निज़ात दिलाने के लिए हर प्रकार से कटिबद्ध हो जाएँ। वस्तुत: स्वतंत्रता को अक्षुण्ण तथा यथावत बनाए रखने के लिए तथा स्वतंत्रता की रक्षार्थ हेतु हमें शाश्वत रूप से सतर्क रहना ही होगा। आज स्वतंत्रता के मूल्य के रूप में राष्ट्रवादी हमसे शाश्वत रूप से सतर्क रहने का आह्वान कर रहे हैं। वस्तुत: भविष्य में भी स्वतंत्रता का आनन्द लेने के लिए हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना ही होगा, इस कथन की सत्यता को हमनें सम्भवत:आज से पूर्व एवं अधिक, कभी भी नहीं सराहा है।

About the Translator

सौरभ अग्रवाल, धातुकीय अभियांत्रिकी, आईआईटी–बीएचयू से स्नातक हैं। वह नियमित स्वैच्छिक रक्तदाता, शोधकर्ता, शिक्षाविद्, लेखक–अनुवादक, कवि एवं राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पूर्व में वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी, नारायणा शिक्षण संस्थान, कानपुर के समूह निदेशक (अकादमिक) आदि पदों पर आसीन रहते हुए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। इसके पूर्व सौरभ अग्रवाल जी द्वारा अनुवादित सात अन्य पुस्तकें ''**मुस्लिम हमलावरों के विरुद्ध शूर हिन्दू प्रतिरोध (636 ई. से 1206 ई. तक)**'', ''**हिन्दू और हिन्दू धर्मः शब्दों के अर्थ और छल**'', ''**मार्क्सवादी–स्तालिनवादी इतिहासकारों का झूठ का मकड़जाल**'', ''**राष्ट्रीय दृष्टि की पुनर्स्थापना**'', ''**मन्ना : एक स्वर्गीय भोजन (यथार्थ या भ्रम?)**'', ''**वे आज कहाँ हैं? (साम्यवाद के कम्युनिस्ट)**'' तथा ''**शिक्षा के प्रति हिन्दू दृष्टिकोण**'' वॉयस ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की जा चुकीं हैं। ''**पश्चिम बंगाल में रक्तिम नक्षत्रोदय**'' वॉयस ऑफ इंडिया के लिए अनुवादक के रूप में सौरभ अग्रवाल जी की आठवीं प्रकाशित पुस्तक है।